राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
2009–10 की बजट घोषणाओं की स्थिति

पैरा संख्या पार्ट संख्या सब पैरा संख्या	बजट घोषणा	प्रगति
166 0 0	राज्य की आई.टी पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक विभाग अपने योजनागत बजट का 3 प्रतिशत भाग विभाग में आई.टी. के प्रयोग एवं कम्प्यूटराईजेशन पर खर्च करेगाा ताकि जनता को सही मायने में ई–गवर्नेंस का लाभ मिल सके। अभी तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हुई है। अतः सभी संबंधित विभागो को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस नीति की पालना करने के लिये निर्देश दिये जा रहे है।	वित्त विभाग तथा अन्य समस्त समक्ष स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 19–11–2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिशानिर्देश पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। तत्पशचात् इसकी निरन्तरता में समस्त राजकीय विभागों द्वारा कम से कम दो नागकिरकोन्मुखी सेवायें चयनित कर सी.एस.सी कियोस्क क माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु परिपत्र जारी कर दिया गया है।
167 0 0	प्रदेश में संबंधित सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलबघ कराने के उद्देश्य से एक नॉलेज बैंक बनाने का निश्यच किया गया है।	स्टेट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाऐं एवं आम नागरिको को उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से वेब साईट http://rajasthan.gov.in पर उपलब्ध समसत सूचनाओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त निम्न सूचनाओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त निम्न सूचनाऐं एवं सेवाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है। • विभिन्न विभागों के 33 आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा • व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की सूचना 283 व्यक्तिगत/सामूहिक लाभ की योजनाओं की जानकारी 36 विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी • विभिन्न विभागों से संबंधित 56 विनियम एवं नीति दस्तावेज • विभिन्न विभागों की नागरिक केन्द्रित सेवाओं का लाभ किस प्रकार उठाया जाऐ इस संबंध में समस्त जानकारी उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों की समस्त अधिकृत वेब साइट में एक ही स्थान से , राज्य पोर्टल से, खर्च की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए राज्य पोर्टल को क्रियाशील कर दिया गया है।

पैरा संख्या पार्ट संख्या सब पैरा संख्या	बजट घोषणा	प्रगति
167 0 0	राज्य में एक आधुनिक स्टेट डॉटा सेन्टर स्थापित किया जायेगा, जिस पर लगभग 50 करोड़ रूपये की लागत आयेगी।	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर का उद्घाटन 15.12.2010 को किया गया।
168 0 0	नागरिकों को सरकारी सेवाएं और सूचनायें ई–मित्र योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में भी 6 हजार 626 कॉमन सर्विस सेन्टर्स स्थापित किये जायेंगे, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को शहरों के समान ही सेवायें सुलभ हो सकेंगी।	यह एक केन्द्र सरकार पोषित परियोजना है जो भारत सरकार द्वारा एन.ई.जी.पी के अर्न्तगत देश के समस्त राज्यों में लागू की जा रही है। सम्पूर्ण राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 6626 कॉमन सर्विस सेन्टर खोलने का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान के समस्त सात संभागों पर इस परियोजना का क्रियान्वयन मैं. सी.एम.एसत्र एवं मै. जूम टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है। आदिनांक (01–07–2011) तक सेवा प्रदाता ऐजेन्सियों द्वारा 3920 ग्रामीण स्तरीय उद्यमी चुन लिये गये है जिनमें से 2547 उद्यमियों ने स्वीकार पत्र हस्ताक्षरित कर दिये है। इनमें से कुल 2247 केन्द्र क्रियाशील है जिनमें से 2093 केन्द्र व्यापार से नागरिक के साथ–साथ सरकार से नागरिक सेवाओं हेतु तैयार है। इनमें से कुल 1626 केन्द्र सरकार से नागरिक सेवाओं हेतु क्रियाशील है।
170 0 0	एस एम एस चिकित्सालय, जयपुर में प्रारम्भ किये गये आरोग्य को अन्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रारंभ किया जायेगा।	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में आरोग्य ऑनलाईन को जयपुर के अतिरिक्त अन्य सभी 5 मेडिकल कॉलेज व उनसे सम्बन्ध 23 अस्पताल तथा 9 जिलो में अस्पताल में लागू किया जायेगा। बजट घोषणा की अनुपालना में सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर व उससे सम्बन्धित 7 अस्पतालों के कम्प्यूटरीकरण हेतु त्रिपक्षिय एमओयू सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, सीडेक व राजकॉम्प के मध्य दिनांक 08–12–2010 को सम्पादित किया गया। इस करार के अनुसार आरोग्य ऑनलाईन इन 7 अस्पतालों में 9 से 12 माह के भीतर क्रियान्वित कर दिया जायेगा।